बावजूद मशीनों की मरम्मत का कार्य गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कराया गया ; और

(ङ) यदि हां, तो गत दो वर्षों में उपर्युक्त मरम्मत कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मरम्मत कार्य कराए जाने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) कोयला मंत्रालय के अन्तर्गत कोई कार्यशालाएं नहीं चलाई जा रही हैं । कोल इंडिया लि० के अंतर्गत कार्यशालाएं सामान्य रूप से चल रही हैं ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान को० इ० लि० कार्यशालाओं तथा मूल उपकरण निर्माताओं (को० ई० एम०) द्वारा मरम्मत (पुनर्वास) किए गए उपकरण की कुल संख्या नीचे दर्शाई गई है :

1990–91	1991–92	1992–93
652	787	649

इसमें से को० ई० एम० ने उपकरण की कुल संख्या के प्रतिवर्ष लगभग 15% उपकरणों की मरम्मत की है ।

(घ) और (ङ) 128 कार्यशालाओं में से केवल 14 क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय कार्यशालाएं हैं जिनमें मरम्मत कार्य किए जाने की क्षमता हैं । कोयला कंपनियां अपेक्षित कार्यशाला/मूलभूत सुविधाओं तथा/अथवा तकनीकी विशेषज्ञता की अनुपलब्धता के कारण उपकरण की मरम्मत के लिए को० ई० एम० की सेवाएं प्राप्त करती हैं ।

पिछले दो वर्षों में को. ई. एम. द्वारा की गई मरम्मत (पुनर्वास) पर श्रमिक प्रभारों के रूप में व्यय की गई कुल राशि नीचे दर्शाई गई है :

(लाख रु० में)

1991–92	1992–93
60.31	49.90

इस उद्देश्य के लिए, फालतू कल-पुर्जों के संबंध में अन्य मद या तो को. इ. लि. के भंडारों से आपूर्ति की गई अथवा उनकी निर्माताओं से खरीदी की गई ।

भूमिगत कोयला खनन संबंधी उपकरणों की अनुपलब्धता

3571. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपेक्षित मशीनों/उपकरणों की कमी होने के कारण भूमिगत मशीनों की उपलब्धता कम रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार खुली खदानों और भूमिगत खदानों में कितनी-कितनी मशीनें कार्यरत थीं और उनका मूल्य कितना था ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस संबंध में विवरण नीचे दिया गया है :

बड़े ओपेनकास्ट खनन उपकरण	31-3-93 की स्थिति के अनुसार कार्यरत मशीनें	अनुमानित कीमत (करोड़ रु० में
ड्रैगलाइन	36	802.85
शावेल	773	1598.20
डम्पर	3249	2048.48
ड्रौजर	767	465.77
ड्रिल	591	425.67
जोड़ :	5416	5348.87

बड़े ओपेन कास्ट खनन उपकरण	31-3-93 की स्थिति के अनुसार कार्यरत मशीनें	अनुमानित कीमत (करोड़ रु० में)
रोड़ हैडर/डिन्टेर	18	45.67
पी० एस० एल० डब्लू०	10	500.00
एल० डी० एल० एडं एल० एच० डी०	465	165.07
जोड़ :	493	710.74

कोयले के स्टाकवार्डों की कमी

3572. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोयले के स्टाकवार्डों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने कोयले के उपयोगकर्ताओं के निकट स्टाकवार्ड स्थापित किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) कोल इंडिया लि० (को.इं.ल.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अभी वह 35 स्टाकवार्डों का संचालन कर रही है, जो कि देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। इनके अतिरिक्त राज्य सरकार के उपक्रम भी कोयला स्टाकयार्ड चलाते हैं । वर्तमान स्टाकयार्ड नीति के अंतर्गत स्टाकवार्डों की स्थापना और प्रबंधन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । इन स्टाकवार्डों को कोयले के प्रेषण के लिए कोयला कंपनियां राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रायोजनों के अनुसार कोयला प्रदान करेंगी । यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे कोयला स्टाकवार्डों की आवश्यकताओं को देखें उन्हें व्यवस्थित करें और उनके लिए कोयले के संचालन का प्रयोजन करें ।

कोल इंडिया लि० ने सभी राज्य सरकारों से सम्पर्क किया है तथा उनसे अनुरोध किया है कि वे उक्त नीति के अंतर्गत स्टाकवार्डों की स्थापना और प्रबंधन का उत्तरदायित्व ग्रहण करें। कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकार अपने-अपने राज्यों में स्टाकवार्डों की स्थापना और उनके प्रबंधन का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए पहले ही सहमत हो गई हैं।